Phones :2048881-2-3
GRAMS : DHARMAJAYA
TELEX : DMC 011 2646

THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.

REGD. OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N.ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(कक्ष भू - प्रबंध),
वन भवन, लिंक रोड नं. 2,
भोपाल।

विषयः– वन मंडल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वन कक्ष क्रमांक RF-1491 के रकबा 40.468 हे. वनभूमि बाक्साइट उत्खनन व विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि. मुम्बई को उपयोग पर देने बाबत् (Online No. FP/MP/MIN/23750/2017)- regarding.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./ 8-10/2021-FC दिनांक 10/10/2023

——0——

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./8-10/2017-FC दिनांक 10/10/2023 से 11 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The State Govt. has not submitted the complete chronological history of the mining lease and reason behind closure of mine on dated 01.12.1998. Further, the State Govt. renewed the mine lease after the gap of 17 years. Therefore, the same needs clarification.	इस खदान के लिये आवेदक तथा राज्य शासन के बीच 100 एकड़ वन भूमि के लिये दिनांक 02.12.1978 को करारनामा हुआ। यह करारनामा स्वीकृत दिनांक 20 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। वर्तमान समय में (खान एवं खनिज अधिनियम में नवकरण प्रक्रिया अनुसार प्रथम नवकरण 20 वर्ष एवं द्वितीय नवकरण 10 वर्ष कुल अवधि 50 वर्ष की व्यवस्था प्रचलित थी) करारनामा की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। जिला बालाघाट तहसील परसवाड (बैहर पुरानी) के ग्राम फण्डकी मोहगांव वन कक्ष क्रमांक 1491 (पुराना 280) में रकबा 100 एकड़ क्षेत्र पर बाक्साइड खनिज का खनिपट्टा दिनांक 02.12.1978 से 01.12.1998 तक स्वीकृत होकर अनुबंधित रहा। पट्टाधारी द्वारा दिनांक 19.11.1997 को निर्धारित समयवधि में खनिपट्टा समाप्ति से एक वर्ष पूर्व खनिपट्टे के नवकरण हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। चूंकि स्वीकृत स्वीकृत खनिपट्टा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व स्वीकृत होकर अनुबंधित रहा है। वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण खनिज विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.04.1998 से वन विभाग को नवकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु खनिपट्टे के नवकरण आवेदन पत्र का निराकरण न होने के कारण आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक

		328/1999 दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2000 को आदेश पारित किये है जिसका आपरेटिव पार्ट निम्नानुसार है :– "It is directed that the competent authority shall forward the application to the Central Government which shall finalise the application for grant of renewal of lease within three months from the date of receipt of the application." इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये थे कि तीन माह के भीतर आवेदक को नवकरण आवेदन पत्र भारत सरकार को भेजा जावे। यदि कोई कमियां हो तो उसकी पूर्ति आवेदक से करायी जावे। आवेदक द्वारा खनिपट्टे का नवकरण न होने तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने पर स्वीकृत खनिपट्टे का खनन कार्य बंद होने की स्थिति में 100.00 एकड़ क्षेत्र का डेडरेंट व सरफेसरंटे, ग्रामीण अवसंरचना राशि नियमित रूप से जमा की जाती रही। नवकरण आवेदन शासन के समक्ष विचाराधीन रहा अवर सचिव म.प्र. भासन खनिज साधन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक एफ 19–5/2015/12–1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 अनुसार खान एवं खनिज अधिनियम (विकास एवं विनियमन) सशोंधन अध्यादेश की धारा 8–ए (6) में प्रावधानित है कि जहॉ खनिज का उपयोग केपटिव प्रयोजन में उसकी अवधि दिनांक 31.03.2030 तक के अलावा भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है उसकी अवधि 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने या मूल स्वीकृति से 50 वर्ष इन में से जो भी बाद में हो तक पट्टा शर्तो के पालन में किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाता है। उक्त प्रावधानों/निर्देश के अनुक्रम में नवकरण आवेदन में किसी प्रकार की कमी न होने से धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि. मुम्बई महाराष्ट्र को स्वीकृत खनिपट्टे की अवधि दिनांक 01.12.2028 तक विस्तारित कर दी गई है। आदेश दिनांक 12.03.2015 के परिपेक्ष में खनिपट्टा की मूल अवधि से 50 वर्ष आगामी अवधि दिनांक 02.12.1998 से 01.12.2028 तक के लिये मूल खनिपट्टा की समयावधि का पूरक अनुबंध दिनांक 25.07.2015 किया गया। यह खदान वर्तमान में वर्ष 1998 के बाद से ही बंद है।

ii	The wildlife management plan has been prepared for a period of 5 years whereas the period of forest land diversion is mentioned as 13 year as per online application. The life of mine is not clear because the user agency has still not uploaded legible copies of approved mine plan. In this backdrop, the State Govt. shall review the wildlife life management plan period keeping in view the life of mine.	वर्ष 2015 में नया MMDR एक्ट प्रभावशील होने के पश्चात राज्य शासन द्वारा इसकी खदान की लीज अवधि मूल दिनांक से 50 वर्ष की मान्य करते हुये इस वर्ष 2028 तक विस्तारीकरण किया है। तत्समय खदान की अवधि 13 वर्ष शेष थी। अतः प्रस्ताव में भाग–1 में स्वीकृति की अवधि 13 वर्ष चाही गई थी। वर्तमान में विस्तारीकरण की प्रक्रिया में लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। खदान की अवधि अब 5 वर्ष की ही शेष है। प्रस्ताव में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना 5 वर्ष की है जो लीज अवधि के समतुल्य है। अतः वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
iii	The Ministry vide letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 has revised the NPV rates. Therefore, the cost benefit analysis needs to be revised keeping in view of revised NPV rates and same needs submission as per the prescribed format given in the Handbook of Guidelines issued by the Ministry vide letter dated 28.03.2019.	भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 में संशोधित नेट प्रजेंट वैल्यू की दरों के अनुसार कास्ट–बेनेफिट एनालिसिस कर लिया गया है, जो परिशिष्ट–3 में संलग्न है।
iv	The copy of the revenue papers of the Non-forest land for Compensatory Afforestation (Form P-II) as submitted are not legible and same needs submission.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि आवेदक के नाम पर है जिसकी फार्म पी–।। की प्रति पोर्टल पर अपलोड है। राजस्व विभाग द्वारा पोर्टल पर भूमि स्वामियों के नाम दर्ज किये जाते हैं जो फार्म पी–।। में रहते हैं। प्रकरण में गैर वनभूमि आवेदक संस्था के प्रतिनिधि के नाम है जिसे सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरांत राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम हस्तांतरित कर इसे संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही औपचारिक स्वीकृति के पूर्व कर ली जायेगी।
v	The suitability certificate of the CA land issued by the concerned DFO has not been found attached and same needs submission.	वन विभाग से संबंधित है।
vi	The user agency has still not uploaded legible copy of approved mining plan in online Part-I and same needs to be uploaded.	आई.बी.एम. (भारतीय खान ब्यूरो) द्वारा माईनिंग प्लान का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसकी अवधि पॉच वर्ष की होती है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत द्वितीय पॉच वर्षों के लिये माईनिंग स्कीम जिसे आई.बी.एम. द्वारा वर्ष 2020 में आर.एम.पी. (रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान) पढ़ा एवं रखा जाने लगा।

		आवेदक संस्था द्वारा अनुमोदित खनिपट्टा का प्रथम पॉच वर्षों हेतु, वर्ष 2013 से 2018 तक का माईनिग प्लान अनुमोदन प्राप्त किया गया। वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि हेतु माईनिंग स्कीम का अनुमोदन प्राप्त किया। वर्तमान में 2023 से 2028 अवधि हेतु आर.एम.पी. (रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान) कार्य में जमा किया जा चुका है। चूंकि कार्य प्रारम्भ न होने के कारण आर.एम.पी. (रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान) आईबीएम में अनुमोदन हेतु जमा किया जा चुका है क्योंकि कार्य प्रारम्भ न होने के कारण पूर्व वृत्त ही है। प्लान प्राप्त होते ही उसकी प्रति पृथक से प्रस्तुत कर दी जावेगी।
vii	The copy of the approval of mining plan uploaded in Part-I revealed that the Mining plan including progressive mine closure plan was valid till 31.03.2023. This needs clarification.	उपरोक्त बिन्दु विवरण के अनुसार माईनिंग प्लान को अनुमोदन की कार्यवाही प्रत्येक 5 वर्ष में की जाना होती है। खदान विस्तारीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। IBM से नवीनीकृत माईनिंग प्लान की प्रति प्राप्त होते ही इसे पृथक से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
viii	As per DSS analysis, it has been reported that the user agency has still not uploaded the correct KML file of proposed forest land for diversion in the online part-I form on the PARIVESH as the total area of KML file uploaded is found to be 41.02 ha instead of 40.468 ha proposed diversion. Moreover, the user agency has not uploaded the KML file of proposed forest land for diversion as per the proposed component wise details and same needs submission.	पोर्टल पर अपलोड की गई KML file तथा आपके द्वारा अवगत कराई गई KML file में मात्र 1.3 प्रतिशत का अंतर है जो मान्य योग्य है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी स्थल निरीक्षण में प्रभावित वनभूमि का रकबा 40.468 हेक्टेयर होना ही अवगत कराया है।
ix	As reported earlier by DSS analysis approximately 1.2 ha area in the Non Forest Land proposed for CA is covered by road, river and water-bodies. However the State Govt. has not measured the actual area available for plantation on ground and has not provided the details of additional NFL required after deducting the area occupied by road, river and water-bodies from the CA land proposed.	वन विभाग से संबंधित है।
x	The State Govt. has not submitted the KML file of proposed Degraded Forest Land where the balance plants will be planted as per Working Plan prescriptions.	वन विभाग से संबंधित है।

xi	It has been informed that the user agency i.e. M/s Dharamji Morarji Chemical Company Limited filed a petition application in the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh vide petition No.328/1999 and the Hon'ble High Court directed Madhya Pradesh Govt. for renewal of mining lease. In this regard, the State Govt. shall submit the details of the said court case along with its present status.	आवेदक संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण दर्ज किया था कि उनकी खदान का नवीनीकरण किया जाये। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने खदान के नवीनीकरण के संबंध में निम्नानुसार आदेश दिया था :– "It is directed that the competent authority shall forward the application to the Central Government which shall finalise the application for grant of renewal of lease within three months from the date of receipt of the application. Needless to emphasise if the application is not in order the State Government may point out the defects to the petitioner and the same shall be removed as directed by the competent authority. In course of hearing it was urged by Mr. Thakur that during the subsistence of the lease the petitioner has excavated certain quantity of Bauxite and hence he may permitted to remove the same. The petitioner may approach the competent authority in this regard and it would by upon the said authority to para appropriate orders in accordance with law." इस प्रकार माननीय न्यायालय में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.12.2000 की प्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(वास्ते मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई)

Phadki Bauxite PROJECT

COST BENEFIT ANALYSIS

PARAMETER FOR EVALUATION OF LOSSES OF FOREST

Table B- Estimation of cost of forest diversion

S. No.	Parameter	Remark
1	Eco system services losses due to proposed forest diversion	Eco system services losses due to proposed forest diversion suggested by the forest classification report of proposed project . Cost of land 40.468 ha x Rs. 1228590= Rs. 497.19 Lacs Eco class III consists of tropical dry deciduous.
2	Loss of animal husbandry productivity including cost of fodder	As per cost of benefit guideline i.e. 10 % of NPV= Rs. 49.72 Lacs per ha.
3	Cost Human Resettlement	There is no human settlement due to proposed proposed SCHEME hence cost of human settlement is NIL.
4	Loss of public facility and administrative infrastructure (road, building schools, dispensaries, electric lines, railways etc.) on forest land if these facilities were diverted due to the project	There is no Loss of public facility and administrative infrastructure (road, building schools, dispensaries, electric lines, railways etc.) on forest land if these facilities were diverted due to the project. No cost has been added on this account.
5	Possession value of forest land diverted.	The possession value of forest land diverted is taken 30% of NPV = Rs. 149.16 lacs
6	Cost of suffering to outsees	Not Applicable
7	Habitat fragmentation cost	Forest land is being acquired for establishing solar power plant. There is no amount taken under this account.

8	Compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost	The cost of Rs. 6 lac per ha taken for compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost. Hence Amount will be 44 (inclusive of RDF area x Rs. 7 = 308 lacs
9	Total cost due to forest land diversion	Total cost due to forest land diversion will be Rs 497.19 + 49.72 + 149.16 + 308 = Rs. 1004.07 lacs

BENEFITS

S. No.	PARAMETER	COST
1	Increase in productivity attribute specified	This Project is conceived to produce Bauxite in Balaghat District. This mine was in operation for a period of 20 years (from the year 1978 to 1998) and a substantial quantity of Bauxite ore is still remaining in this mine.
2	Benefit to Economy	The main objective is to produce bauxite ore. Thus this will provide raw material to a number of industries.
3	Number of populations benefitted	A population of around 3200 will be benefitted directly or indirectly from this mine.
4	Employment potential	During operational stage direct employment to about 250 person upto 05 year and indirect employment to 2750 person shall be generated.
5	Cost of acquisition facility on non-forest land wherever feasible	No human commodity shall be affected due to construction of the project.
6	Loss of (a) Agriculture (b) Animal Husbandry production due to diversion	No loss of agriculture envisaged.
7	Cost of Rehabilitating and displacement	Not applicable. Based on survey it was found that there is no displacement and majority of construction activity/pipeline would have been done underground.
8	Cost of supply of free fuels to workers residing near forest area during period of construction	The labor camp will be facilitated with LPG facility and hence no tree cutting shall be done for fuel wood.
9	Total Benefit due to project	Estimated production from this mine will be around 6.50 lakh tonnes. This will generate revenue of about Rs. 2080 lakhs

Phones 2048881-2-3
GRAMS : DHARMAJAYA
TELEX : DMC 011 2646

THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.
REGD. OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N.ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

Phadki Bauxite PROJECT

Cast Benefit Analysis:-

Cost Benefit Analysis:-

01) Total Benefit Due To Project Rs. 2080 Lakhs
02) Total Annual cost (Expenditure) Rs. 1004.07 Lakhs
03) Benefit Cost Ratio = 1:2.07

Executive Officer

For - DMCC Ltd. Mumbai (M.H.)

मामला क्रमांक W.P.328/99 सन् 200

आदेश पत्रक (पूर्वानुबन्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
14.12.2000		

The petitioner, a registered Company has applied for renewal of mining lease videAnnexure P.3 to the competent authority of the State Government.

The grievance of the petitioner is that the State Government has not forwarded the application to the appropriate authority in the Central Government and, therefore, the prayer of the petitioner has bot been considered.

Having heard Mr.Thakur, learned counsel for the petitioner, Mr.R.S.Patel, learned standing counsel for Union of India and Mr.P.D.Gupta, learned Dy.A.G. for the State Government, it is directed that the competent authority shall forward the application to the Central Government which ~~xxxxxxxxx~~ shall finalise the application for ~~xxxx~~ grant of renewal of lease within three months from the date of receipt of the application.

Needless to emphasise if the application is not in order the State Government may point out the defects to the petitioner and the same ~~which~~ shall be removed as directed by the competent authority.

In course of hearing it was urged by Mr.Thakur

SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR
सत्यमेव जयते

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

मामला क्रमांक .... सन् 200

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

कार्यालयीन टिप्पणी व आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
	that during the subsistence of the lease the petitioner has excavated certain quantity of Boxite and hence he may be permitted to remove the same. The petitioner may approach the competent authority in the regard and it would be upon the said authority to pass appropriate orders in accordance with law.	
	With the aforesaid direction the writ petition stands disposed of.	
	Sd/- Judge	

TRUE COPY
High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR